दिनांक : 08.01.2026 समय : 07.10AM

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी, भोपाल
प्रातःकालीन समाचार

मुख्य समाचार :-

- भारत की जनगणना-2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी, 1 अप्रैल से प्रारंभ होगी घरों की गिनती।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में होंगे शामिल।
- प्रदेष के षासकीय कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारियों को सुबह 10 बजे पहुंचना अनिवार्य, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने दिए निर्देष।
- प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।

जनगणना 2027

केंद्र सरकार ने भारत की जनगणना-2027 के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 दिनों की अवधि में घरों की गिनती का काम किया जाएगा। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के तय कार्यक्रमों के अनुसार घरों की गिनती शुरू होने से 15 दिन पहले स्वयं की गिनती की सुविधा उपलब्ध होगी। देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना की जाएगी। इसके तहत ये आंकड़ें एन्ड्रायड मोबाइल के साथ-साथ आई ओ एस वर्जन से एकत्रित किए जाएंगे। जनगणना का आंकड़ा जमा करने के लिए तीस लाख कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इन कर्मचारियों में एन्यूमेरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज ऑफिसर और प्रधान या जिला जनगणना अधिकारी होंगे। ये लोग आंकडे एकत्रित करने के साथ ही निरीक्षण और जनगणना के संचालन की निगरानी करेंगे।

राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलनः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन में सहभागिता करेंगे। साथ ही असम राज्य के साथ वन्य जीवों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि मध्यप्रदेश और असम राज्य के बीच पूर्व में वन्यजीवों के आदान-प्रदान पर सार्थक विचार-विमर्श हुआ था। इसमें मध्यप्रदेश में विलुप्त जंगली भैंसों के पुनर्स्थापना और गैंडों को मध्यप्रदेश लाने की सहमति बनी थी। साथ ही मुख्य वन्यजीव अभिरक्षण असम की मांग पर बाघ और मगरमच्छ मध्यप्रदेश से असम राज्य को स्थानांतरित करने की सहमति हुई थी।

विकसित भारत जी-राम-जी योजना- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश के सभी गांवों, गरीबों और किसानों के चहुमुखी विकास और जरूरतमंदों को ग्राम स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए ही केन्द्र सरकार द्वारा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानि वीबी जी-राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। 'हर हाथ को काम' मुहैया कराने के लिए इस अधिनियम में एक ग्रामीण परिवार को अब 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा अधिनियम में रोजगार की यह गारंटी मात्र 100 दिन की थी। कल भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता और विलम्बित मजदूरी देने का प्रावधान भी रखा गया है।

धान खरीदी- मंत्री गोविंद सिंह राजपूत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेष में अभी तक 6 लाख 56 हजार 875 किसानों से 43 लाख 17 हजार 504 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 हजार 369 रूपए प्रति क्विंटल है।

यूनिट का गठन

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास का आधुनिकीकरण (एम.सी.ए.डी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने सचिव, जल संसाधन की अध्यक्षता में स्टेट प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट का गठन किया है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य स्तरीय संचालन समिति से प्राप्त नीतिगत्त निर्देशों एवं सुझावों के आधार पर योजना को क्रियान्वित करायेंगे।

मुख्यमंत्रीः शासकीय कार्यालय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि कोविड काल से प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में 5 दिवसीय सप्ताह की व्यवस्था लागू है। इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कार्यालयीन समय को बढ़ाना और सभी के द्वारा उसका अनुसरण आवश्यक है। कल मंत्रालय में वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देष दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में प्रातः 10 बजे से कार्य आरंभ हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सहित अन्य तकनीकी प्रणालियों का सहारा लिया जाए। इससे अनुशासन के साथ कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा।

उज्जैन सिंहस्थ

उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां जारी है। इसी क्रम में कल संभाग आयुक्त आषीष सिंह और जिला कलेक्टर रोषन कुमार सिंह ने प्रमुख धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। इस संबंध में कलेक्टर रोषन कुमार सिंह ने बताया कि-

बाइट-कलेक्टर रोषन कुमार सिंह

केन बेतवा लिंक

छतरपुर जिले के कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कल केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित ग्राम ढोड़न और डुगरिया में जन चौपाल लगाकर मुआवजा पैकेज के वितरण के संबंध में लोगों को जानकारी दी और संवाद किया। साथ ही बताया कि लोगों की समस्याओं और मांगों के समुचित निराकरण के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। जो लगातार भ्रमण कर समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करेगी।

प्रगति रिपोर्ट

शासन में सक्रियता और योजनाओं पर समयबद्ध तरीक़े से अमल के लिए प्रधानमंत्री के अग्रणी प्लेटफॉर्म- प्रगति की अब तक 50 बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस प्लेटफार्म की शुरुआत की थी जिससे परियोजनाओं की स्थिति की तत्क्षण जानकारी ली जाती है। इसकी बैठकों में बुनियादी परियोजनाओँ और लोक शिकायतों की सीधे प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रगति प्लेटफॉर्म से केंद्र और राज्यों के लिए साझा डिजिटल मंच उपलब्ध हुआ है जो सहयोगपूर्ण संघवाद का सशक्त उदाहरण है।

प्रगति प्लेटफॉर्म से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज़ हुई है, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान हुआ है और उत्तरदायित्व की संस्कृति स्थापित हुई है। इस विशेष श्रृंखला में आज एक नज़र अरूणाचल प्रदेश की कामेंग जल विद्युत परियोजना पर-

रिपोर्ट-दीपेंद्र

पुरानी बस संचालन

मध्य प्रदेश राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार यात्री बसें 15 वर्ष से अधिक अवधि में अब नहीं चल सकेंगीं। 15 वर्ष पुरानी बसों के परमिटों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। ग्वालियर संभाग के आयुक्त मनोज खत्री ने कल बस ऑपरेटरों एवं उनके अधिकृत अभिभाषकों की बैठक में स्पष्ट किया कि राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय का पालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल

भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2026 का आठवां संस्करण भारत भवन में 9 से 11 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल डायरेक्टर राघव चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि यह फेस्टिवल देश और विदेश के ख्यातनाम लेखकों, विचारकों, कलाकारों और बुद्धिजीवियों को एक साझा मंच प्रदान करेगा।

मौसम

प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी है। कई जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और कोल्ड-डे जैसी स्थिति बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड ने राजधानी भोपाल में पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठंड को देखते हुए इंदौर, रायसेन, ग्वालियर और नर्मदापुरम सहित कई जिलों में आज भी स्कूल बंद हैं। कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित है।

समाचार संक्षेप में .....

- आगरमालवा जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 16 जनवरी को किया जाएगा।
- उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मंदसौर के मल्हारगढ़ में 9 करोड़ 10 लाख रुपये की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय भवन का भूमि पूजन किया।
- नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
- कटनी जिले में आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्रदान करने हेतु कलेक्टर के निर्देश पर 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- पन्ना टाईगर रिजर्व के गेट स्थल पर आगामी 9 से 15 जनवरी तक मिलेट फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।